भारत-ब्रिटेन समझौते से निर्यातकों और शिल्पियों में छाई खुशी

अब पूर्वांचल के जीआई उत्पादों का बढ़ेगा दबदबा

बदलेगी तस्वीर

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। भारत, ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से पूर्वांचल के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सबसे अधिक लाभ पूर्वांचल के जीआई उत्पादों को मिलेगा।

पूर्वांचल से हर साल करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात ब्रिटेन को होता है। निर्यातकों के अनुसार ब्रिटेन में जीआई उत्पादों पर 12 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था। जो अब शून्य हो गया है। बनारस इंडस्ट्रियल ऐंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जीआई उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य होने से छोटे-मझोले निर्यातकों का कारोबार बढ़ेगा। आर्टिफिशियल ज्वैलरी के कारोबार भी बढ़ेगा।

पूर्वांचल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि पूर्वांचल से हर साल 500-700 करोड़ रुपये का निर्यात वस्त्र उद्योग से जुड़े उत्पादों का होता है। पूर्व अध्यक्ष मुकुंद अग्रवाल ने कहा कि ब्रिटेन में पूर्वांचल के जीआई उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पूर्वांचल निर्यातक संघ के कार्यकारिणी सदस्य विवेक बरनवाल ने कहा कि एफटीए से ब्रिटेन को निर्यात में 15-20 प्रतिशत वृद्धि होगी।

ब्रिटेन में निर्यात होने वाली वस्तुएं: भदोही की कालीन, शैगी (कालीन का एक प्रकार), सूती और ऊनी कालीन, मिर्जापुर की दरी, गाजीपुर की वॉल हैंगिंग, बनारस से गुलाबी मीनाकारी, सिल्क उत्पाद, साड़ियां, ड्रेस मैटेरियल, कुशन कवर, सोफा कवर, परदे, बेडशीट आदि।

पूर्वांचल के कृषि उत्पादों का बढ़ेगा बाजार : इंग्लैंड ने भारत के कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य से 03 फीसदी कर दिया है। एपीडा के डीजीएम सीबी सिंह ने बताया कि कोरोना काल में दो-तीन शिफ्ट में 10 टन बनारसी लंगड़ा आम भेजा गया था। इसकी डिमांड अब भी है। अब सब्जियां और मौसमी फल भी भेजे जा सकेंगे।

अशोक गुप्ता।

विवेक बरनवाल।

मुकेश अग्रवाल।

मुकुंद अग्रवाल।

भदोही : एफटीए डील से कालीन कारोबार भरने लगेगा उड़ान

भदोही, संवाददाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार ट्रैरिफ बढ़ाकर निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि अब भारत-यूके के बीच एफटीए से बड़ी राहत मिली है। इस ट्रेड डील से न सिर्फ कालीन कारोबार को पंख लगेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

सीईपीसी प्रशासनिक समिति के सदस्य असलम महबूब ने बताया कि कॉरपेट पर इम्पोर्ट ड्यूटी आठ से 12 फीसदी थी। बायर पहले 10 से 12 लाख रुपये जमा करते थे। नए ट्रेड डील से कारोबार को ज्यादा फायदा होगा। वरिष्ठ कालीन निर्यातक सुहैल अकबर ने कहा कि कई देशों के बीच युद्ध के हालात ने कारोबारियों को डरा दिया था। नुकसान भी उठाना पड़ा। यूके और ब्रिटेन सरकार के कदम से आगामी दिनों में कारोबार को जो लाभ मिलेगा, उससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्यातक यादवेंद्र राय काका ने कहा, एफटीए से सस्ती कालीन मिलेंगे। साथ ही भारत के कपड़ा, सिल्क समेत अन्य कारोबार को लाभ होगा। ब्रिटेन के कदम से भी लाभः भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भी उद्यमियों ने सराहा। सीईपीसी के आंकड़ों पर गौर करें तो 2024-25 में 867.49 करोड़ का कालीन भारत ने निर्यात किया था।